>

Title: Need to provide special grants for the development of Mahakaushal region in Madhya Pradesh.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जिस समय देश आजाद हुआ और उसके बाद राज्यों का निर्माण हुआ तो उसके पीछे कहीं न कहीं यह भाव था कि देश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो और उसकी मोनेटरिंग भी ठीक तरह से हो सके। इसी तरह से मध्य प्रदेश का भी निर्माण हुआ, पूरे देश का भौगोलिक केन्द्र जिस जगह पर स्थित है, वह मध्य प्रदेश है। उस मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जहां पर है, उसको हम महाकौशल क्षेत्र कहते हैं। पहले इस महाकौशल क्षेत्र में तीन संभाग आया करते थे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें केवल आठ जिले इसमें माने जाते हैं। उसमें मेरा अपना जो लोक सभा क्षेत्र जबलपुर है, उसके साथ, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और कटनी हैं। इनमें से भी जो डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले हैं, ये अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या का जो प्रतिशत है, वह डिंडोरी में 64.48, मंडला में 57.23, सिवनी में 36.78 और बालाघाट में 34.68 है। इसका मतलब यह है कि यह पूरा का पूरा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें अगर जबलपुर को छोड़ दिया जाये तो पूरे महाकौशल क्षेत्र में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, वह भी पूरे प्रदेश के औसत से बहुत कम है।

ऐसे ही पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत है, वह मात्र 53.6 प्रतिशत है, जबकि इस महाकौशल क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत 45.4 से 75.97 प्रतिशत तक आता है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि पूरे देश में कई बार आर्थिक समृद्धि का ढिंढोरा पीटने के लिए आंकड़ों का सहारा लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में जो विकास है, वह कुछ क्षेत्रों तक और कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया है। जबलपुर, जहां से मैं चुनकर आता हूं, उस जबलपुर क्षेत्र की आज तक आजादी के बाद से सर्वाधिक उपेक्षा हुई है। अंग्रेजों के टाइम पर वह जबलपुर शहर उस पूरे मध्य प्रदेश का ही नहीं, बल्कि सी.पी.एन. बरार का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जो आज अत्यन्त पिछड़ा हुआ माना जाता है। कोई भी देश तब तक खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक उसके प्रत्येक क्षेत्र का ठीक तरह से विकास न हो और सभी के साथ न्याय न हो।

हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पिछले 6 सालों में विकास के लिए लगातार प्रयास किये हैं, 2-2 यूनिवर्सिटीज़ की सौगात वहां पर दी है, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्री राकेश सिंह : मैंने आपका संरक्षण मांगा है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उसके बावजूद भी पिछले पांच सालों में विकास के भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी आज भी वहां बहुत कमी है। अगर हमें उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करना है तो उसके लिए वहां पर औद्योगिक विकास, खेती, सिंचाई सुविधाएं, रोजगार के अवसर, इन सब के लिए वृहद स्तर पर इफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा है और उसमें इस क्षेत्र के विकास के लिए 19,303 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज की मांग की है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस पैकेज को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाये और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी बची हुई अवधि में इस पैकेज को शामिल किया जाये। मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हमारे यहां के चार जिले आते हैं, जिनमें यदा-कदा नक्सली वारदातें होती रहती हैं। इससे पहले कि वहां किसी गम्भीर स्थिति का निर्माण हो और उस क्षेत्र को भी हम वैसे ही गम्भीर संकट में घिरा हुआ देखें, उससे पहले ही उस क्षेत्र को विशेष पैकेज देकर उस क्षेत्र के विकास की सार्थक पहल यह सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र,

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला,

श्री वीरेन्द्र कुमार व

श्री के.डी.देशमुख

*m06 श्री राकेश सिंह के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री राम किशुन, कृपया संक्षेप में बोलिये।